न्यूज डायरी

पनामा की जेल में गोलीबारी में 12 कैदियों की मौत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) पनामा सिटी। पनामा की एक जेल में गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 12 से अधिक लोग घायल हो गए। पनामा प्रशासन ने यह जानकारी दी। यह गोलीबारी जेल के एक ब्लॉक में हुई जहां एक ही गिरोह के सदस्यों को रखा गया था। ऐसा लग रहा है कि पनामा सिटी के ला जोयिता जेल में हथियार तस्करी करके लाए गए थे। घटनास्थल से 5 पिस्तौल और तीन राइफल बरामद हुए हैं। नैशनल पुलिस के सहायक निदेशक अलेक्स मुनोज ने बताया कि तस्करी की यह समस्या लंबे समय से चल रही है और कई तरीके हैं जिससे हथियार यहां तक पहुंच जाते हैं। गृह विभाग ने बताया कि इस गोलीबारी में कोई गार्ड या जेल कर्मचारी घायल नहीं हुआ है और न ही कोई जेल से फरार हुआ है।

मैक्रों मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने नाइजर जाएंगे

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों इस महीने की शुरुआत में जिहादी हमले में मारे गए 71 सैनिकों को श्रद्धांजलि देने नाइजर जाएंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने मंगलवार को यह घोषणा की। एलिसी पैलेस ने बताया कि मैक्रों पश्चिमी तिलाबेरी क्षेत्र में 10 दिसंबर को इनेट्स सैन्य शिविर में मारे गए सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस सप्ताह के अंत में राजधानी नियामे जाएंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में बताया कि मैक्रों नियामे में नाइजर के राष्ट्रपति महामदू इसोफोउ से भी मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच 13 जनवरी को दक्षिणी फ्रांस के पाउ नगर में होने जा रहे शिखर सम्मेलन की यधेजना पर बातचीत होगी जिसमें इसोफोउ के अलावा बुर्कीना फासो, माली, चाड और मॉरीतानिया के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे।

नेशनल गार्ड और संदिग्धों के बीच गोलीबारी में आठ लोगों की मौत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) मैक्सिको। मैक्सिको के उत्तरी–मध्य राज्य गुआनाजुआटो में मंगलवार को गोलीबारी में सात बंदूकधारी और नेशनल गार्ड का एक अधिकारी मारा गया। एक अधिकारी घायल भी हुआ है। नेशनल गार्ड ने बताया कि इरापुआटो शहर में राजमार्ग के पास गश्त कर रहे नेशनल गार्ड के दल पर कुछ संदिग्धों ने गोलियां चलाईं जिसका अधिकारियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गुआनाजुआटो अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण कृषि एवं औद्योगिक राज्य है। लेकिन इस साल यहां मैक्सिको के अन्य राज्यों की तुलना में हत्या के काफी अधिक मामले सामने आए हैं। यहां साल के पहले 11 महीने में हत्या के 3,211 मामले सामने आए हैं।

पाकिस्तान ने कश्मीर पर फैलाया नया झूठ

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद–370 को हटाए जाने को लेकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान की सरकार ने बुधवार को कश्मीर के मसले पर अपने मुल्क में एक नया झूठ फैला दिया। हालांकि, यह झूठ उस वक्त तार तार हो गया जब समाचार एजेंसियों ने असलियत को दुनिया के सामने रख दिया। दरअसल, इमरान खान की सरकार ने पाकिस्थान में अपने सरकारी रेडियो चैनल के जरिए यह दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू–कश्मीर के मसले पर एक गोपनीय अनौपचारिक बहस किया। रेडियो चैनल ने अपने विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक क्लोज सेशन में चीन ने जम्मू–कश्मीर के मसले को उठाया।

स्पेस फोर्स गठित करने पर अमेरिकी सीनेट की मुहर

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वाशिंगटन। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने मंगलवार को सालाना रक्षा बजट पर अपनी मुहर लगा दी। इस बजट में स्पेस फोर्स गठित करने का प्रावधान भी किया गया है। इस बजट से जुड़े बिल में अमेरिकी सेना की नई शाखा के तौर पर अंतरिक्ष बल की स्थापना की बात कही गई है। यह वायुसेना के नियंत्रण में रहेगी।

विरोध के बाद चीन ने वापस लिया 'कश्मीर पर चर्चा' वाला प्रस्ताव

यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा चाहता था चीन

विरोध

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

न्यू यॉर्क। कश्मीर की स्थिति पर चीन ने यूनाइटेड नेशंस सिक्यॉरिटी काउंसिल (यूएनएससी) में बंद कमरे में चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा था। सिक्यॉरिटी काउंसिल के सदस्यों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के विरोध के बाद चीन ने अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक, दिसंबर में यूएनएससी के अध्यक्ष बने अमेरिका ने चीन के समर्थन वाला प्रस्ताव रोकने की अगुवाई की। वहीं, फ्रांस ने कहा कि कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। भारत ने इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, भारत सिक्यॉरिटी काउंसिल का समदस्य नहीं है, इसलिए वह चर्चा में शामिल नहीं है। फ्रांस के एक डिप्लोमैटिक सूत्र ने बताया, हमारी पोजिशन बिल्कुल साफ है।

कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से ही देखना होगा। हमने हाल में न्यू यॉर्क सहित कई अवसरों पर यह बात कही है।

भारत के समर्थन में आया ब्रिटेन

यूएनएससी में इस मुद्दे पर ब्रिटेन ने पहली बार भारत का साथ खुले तौर पर दिया है, वहीं यूएनएससी के एक अन्य स्थायी सदस्य रूस ने कहा कि फोरम में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। रूस का कहना था कि अजेंडा में दूसरे अहम वैश्विक मुद्दे होने चाहिए। 15 सदस्यों वाली यूएनएससी में शामिल इंडोनेशिया ने इस बात पर ऐतराज जताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के भारतीय क्षेत्र की ओर सुरक्षा बलों के जमावड़े को चर्चा का आधार क्यों बनाया जा रहा है। इंडोनेशिया ने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है।

एक सूत्र ने बताया कि सीमा के मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आने वाले हैं और चीन ने इससे पहले दबाव बनाने के लिए कश्मीर का प्रस्ताव बढ़ाया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत सरकार के निर्णय के बाद जारी किए गए मानचित्र को देखते हुए चीन चर्चा कराना चाहता था।

भारत पर दबाव बनाना चाहता था चीन: घटनाक्रम से वाकिफ एक शख्स ने बताया, श्अवकाश के कारण सुरक्षा परिषद में कामकाज बंद रहने वाला है। साथ ही, भारत की अमेरिका से 22 वार्ता बुधवार से शुरू होने वाली है और विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत के लिए 21 दिसंबर को वांग यी भारत आने वाले हैं।

ऐसे में यूएनएससी में बंद कमरे में चर्चा पर जोर देने का मकसद केवल यह था कि सीमा मुद्दे को लेकर भारत पर दबाव बनाया जाए। एक अन्य सूत्र ने कहा कि चीन यह दिखाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता था कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत–पाकिस्तान अजेंडा और भारत–चीन सीमा मुद्दा है।

वैज्ञानिक लेखों का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशक है भारतः रिपोर्ट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

वॉशिंगटन। अमेरिका की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत विज्ञान और इंजिनियरिंग विषय पर लिखे गए लेखों को प्रकाशित करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशक है। अमेरिका के नैशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा तैयार डेटा के मुताबिक चीन इस मामले में नंबर एक पर है जो दुनिया भर में छपने वाले वैज्ञानिक लेखों में 20.67 प्रतिशत योगदान देता है।

मंगलवार को जारी किए गए इन आंकड़ों में बताया गया कि 2008 में, भारत ने विज्ञान और इंजिनियरिंग विषय पर 48,998 लेख प्रकाशित किए। यह संख्या 2018 में बढ़ कर 1,35,788 लेखों पर पहुंच गई और अब भारत दुनिया भर में इस विषय पर प्रकाशित होने वाले लेखों में 5.31 प्रतिशत का योगदान देता है।

चीन में, 2008 में 2,49,049 वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए गए जो 2018 में बढ़ कर 5,28,263 हो गए। वैज्ञानिक लेखों के प्रकाशन के मामले में दूसरे नंबर पर अमेरिका (4,22,808) है।

टॉप 10 की सूची में जगह बनाने वाले अन्य देशों में जर्मनी (1,04,396), जापान (98,793), ब्रिटेन (97,681), रूस (81,579), इटली (71,240), दक्षिण कोरिया (66,376) और फ्रांस (66,352) है।

सीरिया में बमबारी में 23 नागरिकों की मौत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) बेरूत। सीरियाई शासन के हवाई हमलों और गोलाबारी में मंगलवार को 23 नागरिक मारे गए। एक मानवाधिकार संगठन ने यह जानकारी दी। माना जा रहा था कि जिहादियों के कब्जे वाला इदलिब क्षेत्र कई महीने पहले हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद सुरक्षित हो जाएगा लेकिन यहां भीषण बमबारी जारी है। सीरियन ऑब्जर्वेट्री फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि इन हमलों में कम से कम 30 लोग घायल हो गए। इनमे से कुछ की हालत गंभीर है।

सऊदी का दबाव? कुआलालंपुर समिट से इमरान खान ने किया किनारा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

19 से 21 दिसंबर तक चलेगा कुआलालंपुर समिट

कुआलालंपुर समिट 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा और इसे मुस्लिम वर्ल्ड में एक नए पावर सेंटर को बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। समिट में तुर्की, कतर, ईरान के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 52 देशों के 450 नेताओं, स्कॉलरों, मौलानाओं और विचारकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान मलयेशियाई पीएम महातिर मोहम्मद की मेजबानी में गुरुवार से होने वाले कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगें। कूटनीतिक सूत्रों ने बताया कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से दबाव बढ़ने के बाद यह फैसला हुआ। इमरान को कुआलालंपुर में ईरान, तुर्की और कतर के नेताओं के साथ मंच साझा करना था।

इसे बड़ी कूटनीतिक नाकामी के तौर पर देखा रहा है क्योंकि मलयेशिया और तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर पूरी तरह पाकिस्तान की भाषा बोला था। मलयेशियाई सरकार के मुताबिक इमरान ने महातिर मोहम्मद को फोन करके अपने फैसले की जानकारी दे दी है।

पाकिस्तान ने अपने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को मलयेशिया भेजने पर भी विचार किया था लेकिन बाद में फैसला हुआ कि कुआलालंपुर समिट से दूर ही रहना है। इमरान और जनरल बाजवा दोनों ने सऊदी अरब और यूएई को मनाने की कोशिशें की लेकिन बात नहीं बनी। हाला ही में बाजवा यूएई गए थे और इमरान सऊदी अरब।

इसलिए समिट को खुद के लिए खतरे के तौर पर देख रहा सऊदी: पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, समिट को सऊदी के नेतृत्व वाले ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को–ऑपरेशन का विकल्प तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

उत्तर कोरिया के खिलाफ पाबंदियां हटाने का अमेरिका ने विरोध किया

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) संयुक्त राष्ट्। अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि वह चीन और रूस के उस मसौदा प्रस्ताव का विरोध करता है जो उत्तर कोरिया के महत्वपूर्ण निर्यातों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को खत्म करने से जुड़ा है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव के समय पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह ऐसे समय लाया गया है जब प्योंगयांग उकसावे वाली कार्रवाई की धमकी दे रहा है और परमाणु निरस्त्रीकरण पर बातचीत करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से मिलने से इनकार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप उन वायदों की दिशा में प्रगति करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जो उन्होंने जून 2018 में सिंगापुर में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ पहले सम्मेलन में किए थे। दोनों नेताओं ने देशों के बीच संबंधों में बड़े परिवर्तन करने, दीर्घकालिक शांति कायम करने और पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। उसने कहा कि लेकिन वह अकेला यह नहीं कर सकता। यह उत्तर कोरिया के लोगों के विदेशों में काम करने पर लगी पाबंदी हटाने से भी जुड़ा है।